आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 17.02.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- कल से शुरू होने जा रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां पूरी, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा – प्रदेश सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है।
- रेलवे, देशभर में 60 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र बनाएगा।
- भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दस टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है।

बजट सत्र

कल से शुरू होने जा रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में आज देहरादून में कार्यमंत्रणा व सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आगामी सत्र के लिए एजेंडा तय किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा।
वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र की समयावधि कम होने पर सवाल खड़े किए हैं। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मूल निवास, भू–कानून, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, गन्ना मूल्य, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्र की समयावधि बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार दबाव बनाए रखेगी।

नीति आयोग कार्यशाला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। वे आज देहरादून में नीति आयोग की ओर से "भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियां" विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 'देश का वॉटर टावर' कहा जाता है और प्रदेश में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने स्प्रिंगशेड एंड रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी– सारा का गठन किया है। इसके माध्यम से, प्रदेश में 5 हजार 500 जमीनी जल स्रोतों और 2 हजार 292 सहायक नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की, कि यह कार्यशाला उत्तराखण्ड ही नहीं, बल्कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
कार्यशाला में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी ने हिमालयी राज्यों में खाली हो रहे गांवों को फिर से पुनर्जीवन दिए जाने के लिए बाहर बस गए लोगों को अपने गांवों में वापस लाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया।

भूमिगत विद्युत लाइन

चम्पावत जिला मुख्यालय में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने का काम शुरू हो गया है। ऊर्जा निगम के सहायक अभियंता संजय भण्डारी ने बताया कि लगभग साढ़े सत्रह करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे इस कार्य के पूरा होने के बाद नगर क्षेत्र की जनता को तारों के जाल से मुक्ति मिलेगी।

रेलवे योजना

रेलवे ने देशभर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पीक सीजन के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके सुचारू आवागमन की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले एक सप्ताह तक, शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक, प्लेटफार्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं, प्रयागराज से पवित्र संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए कल प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से तीन सौ अड़तीस विशेष रेलगाड़ियां संचालित की गईं।

इसरो

भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दस टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। इस उन्नत प्रणाली का डिजाइन और निर्माण करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन– इसरो न केवल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है, बल्कि "आत्मनिर्भर भारत स्पेस" पहल के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। इसे इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार किया है।

रेल लाइन

बागेश्वर जिले के खोली के ग्रामीणों ने टनकपुर–बागेश्वर रेल लाइन के लिए रेलवे स्टेशन और कॉलोनी के सर्वे का विरोध किया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उनका रेलवे लाइन को लेकर कोई विरोध नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनके गांव से होकर रेलवे लाइन जाती है, तो उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। लेकिन गांव की कृषि भूमि पर रेलवे स्टेशन और कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। उनका कहना है कि ग्रामीण अपनी उपजाऊ जमीन पहले ही बेस अस्पताल, खेल स्टेडियम आदि के लिए दे चुके हैं। अब उनके पास जमीन आधी हो गई है। वहीं, इस मामले में जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कहा कि रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों की बैठक कराकर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

जन समस्याएं

टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले के जौनपुर विकासखंड के सौंग बांध से प्रभावित रगड़गांव, घुड़सालगांव, खाली डांडा लग्गा सौंदणा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज रगड़गांव में शिविर लगाकर इस संबंध में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने प्रभावित को आश्वासन दिया कि उनकी हर संपत्ति का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी परियोजना हित में जमीन देने वाले काश्तकारों की हरसंभव मदद के निर्देश दिए।

जन संवाद कार्यक्रम

रुद्रप्रयाग के मुख्य विकास अधिकारी डॉ जी.एस. खाती की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 07 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज समस्याओं की समीक्षा भी की। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि एल–1 स्तर पर कुल 149, जबकि एल–2 स्तर पर 27 समस्याएं निस्तारण के लिए लंबित हैं। उन्होंने इन समस्याओं को त्वरित निस्तारित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए और सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए।